



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]

No. 131]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2003/फाल्गुन 30, 1924

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2003/PHALGUNA 30, 1924

वित्त और कम्पनी कार्य बंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण)

(सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

आधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2003

सं. 01/2003-एएआर

सा.का.नि. 229(अ).— अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 28ड और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 23ज के अनुसरण में, उक्त अधिनियमों के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस प्रक्रिया का नाम अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (प्रक्रिया), 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं – इस प्रक्रिया में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) “अग्रिम विनिर्णय” से, यथास्थिति, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 28ड के उपखंड (ख) या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 23क के उपखंड (ख) में यथापरिभाषित अग्रिम विनिर्णय अभिप्रेत है ;

(ख) “आवेदक” से, यथास्थिति, उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28ड के उपखंड (ग) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन आवेदन अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत, जहाँ संदर्भ में अनुज्ञात हो, प्रक्रिया 5 में निर्दिष्ट प्रकृति के सभी आवेदन, याचिकाएं और अभ्यावेदन भी हैं ;

(ग) “आवेदन” से, यथास्थिति, उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (1) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन आवेदन अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत, जहाँ संदर्भ में अनुज्ञात हो, प्रक्रिया 5 में निर्दिष्ट प्रकृति के सभी आवेदन, याचिकाएं और अभ्यावेदन भी हैं ;

(घ) “प्राधिकृत प्रतिनिधि” से --

- (i) आवेदक के संबंध में, वही अर्थ होगा जो, यथास्थिति, उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 146क या उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35थ के अधीन उसका है ;
- (ii) आयुक्त के संबंध में, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है -

 - (क) जो आयुक्त द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है ; या
 - (ख) जिसे प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में आयुक्त के लिए उपसंजात होने, अभिवाक् करने और कार्य करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है या जिसे केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है ;

- (ड) “प्राधिकरण” से उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28च के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय-प्राधिकरण अभिप्रेत है ;
- (च) “अध्यक्ष” से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (छ) “आयुक्त” से अभिप्रेत है :

 - (i) यथास्थिति, उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा-शुल्क आयुक्त या उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त ; या
 - (ii) किसी आवेदक की बाबत केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा डस निमित्त पदाभिहित आयुक्त ;

- (ज) “सदस्य” से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है ;
- (झ) “नियम” से, यथास्थिति, सीमा-शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियम, 2002 या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियम, 2002 अभिप्रेत है ;
- (ञ) “सचिव” से प्राधिकरण के सचिव के रूप में पदाभिहित सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ में ऐसा अपेक्षित हो, सचिव को उसके कृत्यों में सहायता करने के लिए नियुक्त सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अपर आयुक्त तथा सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त भी है ;
- (ट) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषेत नहीं किए गए हैं किंतु, यथास्थिति, उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम या उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वहीं अर्थ हैं जो अधिनियम में उनके हैं।

3. प्राधिकरण की भाषा -- (1) प्राधिकरण की भाषा साधारणतया अंग्रेजी होगी :

परंतु यह कि प्राधिकरण पक्षकारों के अनुरोध पर अपने समक्ष कार्यवाहियों में उस सीमा तक हिंदी के प्रयोग की अनुमति दे सकेगा, जो वह उपयुक्त और व्यावहारिक समझे ।

(2) जहां कोई दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी से भिन्न किसी भाषा में है वहां उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी फाइल किया जाना चाहिए ।

4. प्राधिकरण की शक्तियां – प्राधिकरण, यथास्थिति, उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (1) या उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ग की उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन और अंतर्वर्ती, आनुषंगिक या प्रासंगिक प्रकृति के ऐसे अन्य आवेदनों, याचिकाओं और अभ्यावेदनों की सुनवाई और उनका अवधारण करेगा, जो आवेदन के पूर्ण और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक हों, जैसा अध्यक्ष साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

5. कठिनाई दूर करने की शक्ति – यदि प्राधिकरण के किसी आदेश को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो प्राधिकरण ऐसा आदेश पारित करने से छह मास की अवधि के भीतर, स्वप्रेरणा से या आवेदक अथवा आयुक्त द्वारा किए गए आवेदन पर कठिनाई को उस रीति में दूर कर सकेगा, जो उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या उनके अधीन बनाए गए नियमों के संपर्कों से असंगत न हो।

6. सचिव की शक्तियां और कृत्य – (1) प्राधिकरण के अभिलेख सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा जो इस प्रक्रिया के अधीन या अध्यक्ष द्वारा पृथक् आदेश द्वारा उसे संपी जाए।

(2) प्राधिकरण की शासकीय मुद्रा सचिव की अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(3) सचिव की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-

(i) प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए गए सभी आवेदनों को प्राप्त करना ;

(ii) आवेदनों की यह पता लगाने के लिए संबीक्षा करना कि क्या वे, यथास्थिति, उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम या उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और प्रक्रिया के अनुसूच्य हैं ;

(iii) ऐसे आवेदन में त्रुटियों को पक्षकारों को बताना और उन्हें युक्तियुक्त अवसर प्रदान करके उनसे त्रुटियों को दूर करने की अपेक्षा करना और जहां दिए गए समय के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता है, वहां प्राधिकरण के आवश्यक आदेश प्राप्त करना ;

(iv) अध्यक्ष के परामर्श से आवेदनों के संबंध में सुनवाई की तारीख नियत करना और उसके के लिए सूचनाएं जारी करने का निदेश देना ;

(v) सूचनाओं या अन्य आदेशिकाओं को तामील के लिए जारी करना और यह सुनिश्चित करना कि उनकी पक्षकारों को उचित रूप में तामील हो ;

(vi) किसी व्यक्ति की, जिसके अंतर्गत आयुक्त या कोई अन्य प्राधिकरण भी है, अभिलेख से अभिरक्षा मंगाना ;

(vii) प्राधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण अनुज्ञात करना ;

(viii) प्राधिकरण द्वारा निदेश के अनुसार, प्राधिकरण के अभिलेखों के किसी औपचारिक संशोधन को अभिलेख पर लाना ;

(ix) पक्षकारों को प्राधिकरण के आदेशों की अनुप्रमाणित प्रतियां प्रदान करना ;

(x) पक्षकारों को नियमों के अनुसार, कार्यवाहियों में फाइल किए गए दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां प्रदान करना ;

(xi) कार्यवाहियों के किसी पक्षकार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की दशा में, विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाना और मामले के हक में ऐसे समुचित संशोधन करना जो प्रक्रिया में निर्दिष्ट अन्य स्थितियों में आवश्यक हों :

(xii) ऐसे किन्हीं अभिलेखों का, जो प्राधिकरण द्वारा किसी विनिश्चय पर पहुंचने के लिए सुसंगत समझे जाएं, अध्ययन करना या अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करके अध्ययन करना :

परन्तु यह कि ऐसा कोई अध्ययन केवल प्राधिकरण के आदेशों पर ही किया जाएगा ।

(xiii) किसी ऐसे माल के, जो किसी आवेदन की दशा में सुसंगत समझा जाए, तकनीकी, रासायनिक या बाजारी मूल्यांकन की मांग करना । उस दशा में, जहां ऐसी जांच प्राधिकरण के सचिव द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा आवेदक की प्रसुविधाओं या किसी अन्य स्थान का दौरा करना आवश्यक बनाती है वहां यात्रा के लिए व्यय, अन्य आनुषंगिक व्यय और/या किन्हीं वृत्तिक फीसों का संदाय आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसी कोई जांच केवल प्राधिकरण के आदेशों पर ही की जाएगी ।

7. सूचनाओं, आदि को हस्ताक्षरित किया जाना - (1) प्राधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली किसी अध्येक्षा, निदेश, पत्र, प्राधिकार या लिखित सूचना को सचिव द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(2) उक्त प्रक्रिया (1) की कोई बात ऐसी किसी अध्येक्षा या निदेश पर लागू नहीं होगी, जिसे प्राधिकरण सुनवाई के अनुक्रम में किसी आवेदक या किसी आयुक्त या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को जारी करे ।

8. सूचनाओं की तामील का ढंग - ऐसी प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज को, जो किसी व्यक्ति पर तामील किए जाने या परिदृष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित है, आदेशिका तामीलकर्ता द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के पते पर भेजा जा सकेगा या तामील के लिए उसके द्वारा दिए गए फैक्स नं. पर फैक्स किया जा सकेगा या ऐसे स्थान पर भेजा जा सकेगा जहां व्यक्ति या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि सामान्यतः निवास करता है या कारबार चलाता है या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है ।

9. आवेदन फाइल करने के लिए प्रक्रिया - (1) कोई आवेदन, सीमा-शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियम, 2002 के प्ररूप एआर (सी.श.) या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियम, 2002 के प्ररूप के एआर (के.उ.श.) में चार प्रतियों में किया जाएगा और उसे स्वयं आवेदक द्वारा या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा या सचिव के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, दो हजार पाँच सौ भारतीय रुपए की फीस सहित भेजा जाएगा, जो “अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण” के पक्ष में नई दिल्ली में संदेय एक मांग देय ड्राफ्ट के रूप में होगी ।

(2) आवेदन, इसका सत्यापन और इसके साथ लगे उपाबंध, विवरण तथा दस्तावेज उस शीति में हस्ताक्षरित किए जाएंगे, जो उप प्रक्रिया (1) में निर्दिष्ट नियमों में उपवर्णित है ।

परन्तु यह कि जहां आवेदन या अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति, उक्त नियमों के अधीन इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत होने का दावा करता है, वहां आवेदन के साथ उसे हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करने वाला मुख्यालयामा और एक शपथपत्र संलग्न होगा, जिसमें उन अपरिहर्य कारणों को उपवर्णित किया जाएगा जो उसे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए हकदार बनाते हैं ।

(3) उप-प्रक्रिया (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया आवेदन उस तारीख को दिया गया समझा जाएगा जिस तारीख को वह प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त किया जाता है।

(4) यदि आवेदक का भारत में आधार नहीं है तो वह आवेदन के उपांचं 1 में निम्नलिखित उपदर्शित करेगा :-

(क) किसी भी देश में उसका मुख्यालय,

(ख) वह स्थान, जहाँ उसका कार्यालय और आवास भारत में अवस्थित है या अवस्थित होने की संभावना है, और

(ग) भारत में उसके प्रतिनिधियों के, यदि कोई हों, नाम और पते, जो उसकी ओर से सूचनाएं और पत्र प्राप्त करने और कार्य करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(5) सचिव, आवेदक को उसका आवेदन किसी भी रीति में त्रुटिपूर्ण होने पर त्रुटियों को उतने समय में दूर करने के लिए वापस भेज सकेगा, जितना वह अनुज्ञात करे।

10. प्राधिकरण के समक्ष अतिरिक्त तथ्यों का प्रस्तुत किया जाना

(1) प्राधिकरण, स्वविवेकानुसार आवेदक को ऐसे अतिरिक्त तथ्य प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकता या उससे अपेक्षा कर सकेगा जो अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाने में उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

(2) जहाँ प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान एक ऐसे तथ्य का अभिकथन किया जाता है जो अभिलेख द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता या जो अभिलेख के विरुद्ध है, वहाँ उसे स्पष्टः और संक्षिप्तः कथित किया जाएगा और वह सम्यक्तः शपथित शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा।

11. आवेदन में अंतर्विष्ट प्रश्न - आवेदक, प्राधिकरण की इजाजत के बिना, किसी ऐसे अतिरिक्त प्रश्न के समर्थन में प्रार्थना नहीं करेगा या उसकी सुनवाई नहीं होगी जो आवेदन में उपवर्णित नहीं है, किन्तु आवेदन पर विनिश्चय करने में प्राधिकरण, स्वविवेकानुसार उपवर्णित प्रश्नों के सभी पहलुओं पर विचार करेगा जो उसके द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत प्रश्न के सार पर विनिर्णय सुनाने के लिए आवश्यक हो।

12. सुनवाई की तारीख और स्थान का अंधिसूचित किया जाना - (1) जहाँ उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (1) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ग की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन, किसी आवेदक से प्राप्त होता है और अधिनियम तथा तद्वीन बनाए गए नियमों और प्रक्रिया के उपबंधों के अनुसार कोई आयुक्त पदाभिहित नहीं किया गया है, वहाँ आवेदन और उसके संलग्नकों की एक प्रति बोर्ड को अग्रेषित की जाएगी जिसमें दो सप्ताह के भीतर आवेदन के प्रयोजन के लिए आयुक्त विनिर्दिष्ट या पदाभिहित करने की अपेक्षा की जाएगी जिसके न हो सकने पर उस आवेदन पर आयुक्त की सुनवाई के बिना विनिश्चय किया जा सकेगा।

(2) उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ज की उपधारा (1) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 23ग की उपधारा (1) के अधीन ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर, जिसके संबंध में ऐसे अधिनियमों और तद्वीन बनाए गए नियमों तथा प्रक्रिया के उपबंधों के अनुसार, आयुक्त अभिहित किया गया है, प्राधिकरण आवेदन की सुनवाई की तारीख और स्थान अंधिसूचित करेगा और आवेदन की एक प्रति आयुक्त को अग्रेषित करेगा, जिसमें मामले के सुरांगत अभिलेख और आवेदन की अंतर्वस्तु पर उसकी टिप्पणी, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने की और यदि वह सुना जाना चाहता है तो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि को नामनिर्देशित करने की अपेक्षा की जाएगी।

13. प्राधिकार का फाइल किया जाना - सुनवाई में आवेदक की ओर से उपसंजात होने वाला प्राधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई प्रारंभ होने के पूर्व, एक दस्तावेज फाइल करेगा जिसमें आवेदक की ओर से उपसंजात होने के लिए उसे प्राधिकृत किया गया हो और यदि वह आवेदक का नातेदार है तो उस दस्तावेज में आवेदक के साथ उसकी नातेदारी की प्रकृति अथवा यदि वह आवेदक द्वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति है तो वह पद, जिसपर उस समय वह नियोजित है, कथित होगा ।

14. आवेदक की मृत्यु आदि के बाद कार्यवाही का जारी रहना - जहां आवेदक की मृत्यु हो जाती है या कंपनी की दशा में उसका परिसमाप्त या विघटन अथवा विभाजन या समामेलन हो जाता है या वह किसी अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकार में आ जाती है अथवा समाप्त हो जाती है तो आवेदन का उपशमन नहीं होगा और जहां प्राधिकरण यह समझता है कि परिस्थितियां इसे न्यायोचित ठहराती हैं, वहां इस नियमित आवेदन करने पर कार्यवाहियों को आवेदक के, यथास्थिति, निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि या परिसमाप्त, रिसीवर, समनुदेशिती द्वारा जारी रखने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

15. आवेदन की सुनवाई - (1) प्राधिकरण, नियत तारीख को या किसी अन्य दिन को, जिसको सुनवाई स्थगित की जाए, ऐसे मामलों में आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की सुनवाई करेगा जिनमें आवेदन को नामंजूर करने का प्रस्ताव है या आवेदक सुनवाई का अवसर चाहता है या चाहा है । प्राधिकरण, आयुक्त या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की भी सुनवाई कर सकता है, यदि वह अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाने के पूर्व यह आवश्यक समझता है ।

(2) समुचित मामलों में प्राधिकरण, किसी व्यक्ति से ऐसी सामग्री प्रदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे वह विनिश्चय करने में प्राधिकरण की सहायता के लिए आवश्यक समझे ।

(3) प्राधिकरण, ऐसी शर्तों पर, जैसी मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों, आवेदन की सुनवाई स्थगित कर सकेगा ।

16. आवेदन की एक-पक्षीय सुनवाई - जहां नियत तारीख को या किसी अन्य दिन को, जिसको सुनवाई स्थगित की जाती है, आवेदक या आयुक्त सुनवाई के लिए अपेक्षा किए जाने पर भी स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपसंजात नहीं होता है, वहां प्राधिकरण आवेदन को गुणाग्रण के आधार पर एक पक्षीय रूप से निपटा सकेगा :

परन्तु यह कि जहां आवेदन यथा उपरोक्त रूप में निपटाया गया है और यथास्थिति, आवेदक या आयुक्त आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आवेदन करता है और प्राधिकरण का यह समाधान कर देता है कि जब सुनवाई के लिए उसे बुलाया गया था तब उपसंजात न होने के लिए पर्याप्त कारण था तो प्राधिकरण विष्क को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने का आदेश दे सकेगा और आवेदन को नए सिरे से सुनवाई के लिए पुनः स्थापित कर सकेगा ।

17. आदेश का उपांतरण - जहां प्राधिकरण को निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय को प्रभावित किए जाने से पूर्व स्वप्रेरणा से या आवेदक अथवा आयुक्त द्वारा अभ्यावेदन किए जाने पर या अन्यथा यह पता चलता है कि ऐसी विधि या तथ्यों में कोई परिवर्तन हो गया है, जिनके आधार पर विनिर्णय सुनाया गया था, वहां प्राधिकरण आवेदक और आयुक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात करने के पश्चात् आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को इस प्रकार उपांतरित कर सकेगा, जैसा वह समुचित संमझे ।

18. भूलों की परिशुद्धि - (1) प्राधिकरण अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशुद्धि के लिए उसके द्वारा पारित किसी आदेश का, निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए विनिर्णय को प्रभावी किए जाने से पूर्व संशोधन कर सकेंगा ।

(2) ऐसा संशोधन स्वप्रेरणा से किया जा सकेगा या तब किया जा सकेगा जब आवेदक या आयुक्त द्वारा भूल उसकी सूचना में लाई जाए, किन्तु ऐसा केवल आवेदक या आयुक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात ही किया जाएगा ।

19. अभिलेख का संशोधन - यदि प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर यह प्रतीत होता है कि अभिलेखों में कोई तथ्य संवंधी या तात्परिक गलती है तो आवेदक और आयुक्त को सुने जाने के पश्चात् उसका संशोधन किया जाएगा ।

20. अतिरिक्त प्रमाणित प्रतियां प्रदाय करने के लिए फीस - (1) सचिव, आवेदक या आयुक्त को, उनमें से किसी के द्वारा लिखित अनुरोध किए जाने पर दस्तावेजों या आदेशों की अतिरिक्त प्रमाणित प्रतियां दिए जाने का आदेश कर सकेगा ।

(2). आवेदक को अतिरिक्त प्रमाणित प्रतियां प्रदाय करने के लिए प्रति बनाने की फीस तीन रूपए प्रति पृष्ठ की दर से प्रभारित की जाएगी और ऐसी फीस नकद में अग्रिम रूप में संदत्त की जाएगी ।

21. अभिलेखों का निरीक्षण और उसके लिए फीस - (1) आवेदक या आयुक्त या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को, उसके द्वारा सचिव को लिखित में आवेदन किए जाने पर, मामले के अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी : परंतु यह कि केवल उन दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुज्ञा दी जाएगी, जिनका प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में आश्रय लिया गया है ।

(2) निरीक्षण की अनुज्ञा केवल प्राधिकरण के किसी अधिकारी की उपस्थिति में ही दी जाएगी और आवेदक को निरीक्षण के नोट बनाने की अनुमति होगी किन्तु किसी दस्तावेज की प्रतियां लेने की अनुमति नहीं होगी ।

(3). प्राधिकरण के अभिलेखों के निरीक्षण के लिए आवेदक से निम्नानुसार फीस प्रभारित की जाएगी :-

(क) पहले एक घंटे या उसके भाग के लिए एक सौ रूपए ; और

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त घंटे या उसके भाग के लिए पचास रूपए ।

(4) निरीक्षण के लिए फीस नकद में अग्रिम रूप में दी जाएगी ।

22. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय को शून्य घोषित किया जाना - (1) जहां सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा या अन्यथा प्राधिकरण को यह अभ्यावेदन किया जाता है कि उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28ज्ञ की उपधारा (6) के अधीन या उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 28घ की उपधारा (6) के अधीन उसके द्वारा सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय आवेदक द्वारा कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन से प्राप्त किया गया है, वहां ऐसा अभ्यावेदन चार प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ कपट या दुर्व्यपदेशन को तथा साथ ही कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन के दावे को सिद्ध करने वाले साक्ष्यों की विशिष्टियों को भी सम्मिलित करने वाला तथ्यों का एक विवरण लगा होगा ।

(2) ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर आवेदक को एक सूचना जारी की जाएगी, जिसके साथ खंडन किए जाने के लिए अभ्यावेदन की एक प्रति भी होगी और यथास्थिति, उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 28ज्ञ की उपधारा (2) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23घ की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने से पूर्व आवेदक तथा आयुक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात किया जाएगा ।

23. कार्यवाहियों का जनता के लिए खुला न होना - प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों जनता के लिए खुली नहीं होंगी और प्राधिकरण की अनुमति के बिना आवेदक, आयुक्त या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अन्य कोई व्यक्ति ऐसी कार्यवाहियों के दौरान उपस्थित नहीं रहेगा ।

24. आदेशों का प्रकाशन - प्राधिकरण के ऐसे आदेशों को, जिन्हें अध्यक्ष किसी प्रमाणिक रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशन के लिए उचित समझता है, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें अध्यक्ष विनिर्दिष्ट करे, ऐसे प्रकाशन के लिए जारी किया जाएगा ।

25. आदेशों का अधिप्रमाणन और उनकी संसूचना - (1) प्राधिकरण का प्रत्येक आदेश सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस पर प्राधिकरण की शासकीय मुद्रा लगी होगी ।

(2) प्राधिकरण के ऐसे आदेश की एक प्रमाणित प्रति, आवेदक और आयुक्त को, सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों से संसूचित की जाएगी और उस पर प्राधिकरण की शासकीय मुद्रा लगी होगी ।

26. प्राधिकरण की कार्यवाहियाँ - (1) जब अध्यक्ष से भिन्न प्राधिकरण के एक या दोनों सदस्य अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है अथवा सदस्यों के पदों में कोई रिक्ति या रिक्तियाँ होने की दशा में और जब किसी कारणवश मामले को स्थगित न किया जां सकता हो तो अकेला अध्यक्ष या अध्यक्ष और शेष सदस्य प्राधिकरण के रूप में कृत्य कर सकेंगे ।

(2) उस मामले में जहां किसी आवेदन पर सुनवाई करने वाले सदस्यों की राय में मतभेद हो, वहां उपप्रक्रिया (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदस्यों के बहुमत की राय अभिभावी होगी और प्राधिकरण के आदेश सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे किन्तु बहुमत के विचार से विस्मित होने वाला कोई सदस्य अपने कारण पृथक् रूप से लेखबद्ध कर सकेगा ।

(3) जहां अध्यक्ष और उक अन्य सदस्य उपप्रक्रिया (1) के अधीन किसी मामले की सुनवाई करते हैं और उनकी राय भिन्न-भिन्न है तो अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी ।

27. अन्य आवेदन के मामले में प्रक्रिया - उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 23ज की उपधारा (1) या उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 23क की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की सुनवाई और निपटान के लिए इन प्रक्रिया संबंधी नियमों में अंतर्विष्ट उपबंध, प्राधिकरण के समक्ष अन्य सभी आवेदनों, याचिकाओं और अभ्यावेदनों की सुनवाई और निपटान को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

28. पोशाक विनियम - (1) प्राधिकरण के समक्ष कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि ऐसी पोशाक में उपस्थित होगा, जो सक्षम वृत्तिक निकाय, यदि कोई है, द्वारा उसकी वृत्ति के सदस्यों के लिए विहित हो ।

(2) प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले सभी अन्य व्यक्ति समुचित पोशाकों में होंगे ॥

[फा. सं. 16/02/2002-एएआर]

विजय लक्ष्मी शर्मा, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Revenue)

(AUTHORITY FOR ADVANCE RULINGS

(CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2003

No. 01/2003-AAR

G.S.R. 229(E).— In pursuance of section 28M of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 23H of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Authority for Advance Rulings hereby makes the following rules to regulate its own procedure in all matters arising out of the exercise of its powers under the said Acts, namely :-

1. Short title and commencement. - (1) These rules, may be called the Authority for Advance Rulings (Procedural) Rules, 2003

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “advance ruling” means an advance ruling as defined in sub-clause (b) of section 28E of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the said Customs Act) or sub-clause (b) of section 23A of the Central Excise Act, 1944, (1 of 1944) (hereinafter referred to as the said Excise Act) as the case may be;

(b) “applicant” means an applicant as defined in sub-clause (c) of Section 28E of the said Customs Act or sub-clause (c) of section 23A of the said Central Excise Act, as the case may be;

(c) “application” means an application under sub-section (1) of section 28H of the said Customs Act or under sub-clause (1) of section 23A of the said Central Excise Act, as the case may be, but shall include, where the context permits, all applications, petitions, and representations of the nature referred to in rule 5;

- (d) "Authorised representative",-
- (i) in relation to an applicant, shall have the meaning assigned to it under section 146A of the said Customs Act or under section 35Q of the said Central Excise Act, as the case may be ;
- (ii) in relation to the Commissioner, means a person –
- (a) authorized in writing by the Commissioner; or
- (b) appointed by the Central Government as authorized representative or authorized by the Central Board of Excise & Customs to appear, plead and act for the Commissioner in any proceeding before the Authority;
- (e) "Authority" means the Authority for Advance Rulings constituted under section 28F of the said Customs Act read with section 23H of the said Excise Act;
- (f) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;
- (g) "Commissioner" means,-
- (i) the Commissioner of Customs under the said Customs Act or the Commissioner of Central Excise under the said Central Excise Act, as the case may be ; or
- (ii) the Commissioner designated by the Central Board of Excise and Customs in this behalf in respect of an applicant ;
- (h) "Member" means a member of the Authority and includes the Chairperson;
- (i) "Rule" means the Customs (Advance Rulings) Rules, 2002 or the Central Excise (Advance Rulings) Rules, 2002, as the case may be;
- (j) "Secretary" means a Commissioner of Customs and Central Excise designated as the Secretary of the Authority and includes an Additional Commissioner of Customs and Central Excise and Deputy Commissioner of Customs and Central Excise appointed to assist the Secretary in his functions where the context so requires;

(k) Words and expressions used and not defined herein but defined in the said Customs Act or the said Central Excise Act, as the case may be, shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. Language of the Authority. - (1) The language of the Authority shall ordinarily be English :

Provided that the Authority may, at the request of the parties, permit the use of Hindi in the proceedings before it to the extent it may consider appropriate and practical.

(2) Where any document is in a language other than English or Hindi, an English translation thereof should also be filed along therewith.

4. Powers of the Authority. - The Authority shall hear and determine the application made under sub-section (1) of section 28H of the said Customs Act or sub-section (1) section 23C of the said Central Excise Act, as the case may be, and such other application, petitions and representations of an interlocutory, incidental or ancillary nature as may be necessary for a complete and effective disposal of the application, as the Chairperson may by general or special order direct.

5. Power to remove difficulty. - If any difficulty arises in giving effect to any order of the Authority, the Authority may, within a period of six months of passing of such order on its own motion or on an application made by the applicant or the Commissioner, which is not inconsistent with the provisions of the said Customs Act or Central Excise Act or rules made thereunder, remove difficulties.

6. Powers and function of the Secretary. - (1) The Secretary shall have the custody of the records of the Authority and shall exercise such other functions as are assigned to him under this procedure or by the Chairperson by separate order.

(2) The official seal of the Authority shall be kept in custody of the Secretary,

(3) The Secretary shall also have the following powers and duties, namely:-

- (i) to receive all applications filed before the Authority;
- (ii) to scrutinize the applications to find out whether they are in conformity with the said Customs Act or the said Central Excise Act, as the case may be, or the rules made thereunder and the procedure;
- (iii) to point out defects in such application to the parties and require them to remove the defects by affording them a reasonable opportunity to do so and, where, within the time granted, the defects are not removed, to obtain necessary orders of the Authority;
- (iv) to fix the date of hearing for the applications in consultation with the Chairperson and direct the issue of notices therefor;
- (v) to issue the service of notices or other processes and to ensure that the parties are properly served;
- (vi) to requisition records from the custody of any person including a Commissioner or any other Authority;
- (vii) to allow inspection of records of the Authority;
- (viii) to bring on record any formal amendment of the records of the Authority as directed by the Authority;
- (ix) to grant certified copies of the orders of the Authority to the parties;
- (x) to grant certified copies of documents filed in the proceedings to the parties in accordance with the rule;
- (xi) to bring on record legal representatives, in case of death or retirement of any party to the proceedings and to make such appropriate amendments in the cause title as may necessary in other situations referred to in procedure;
- (xii) to study or cause to study by deputing officers under his control any records which may be considered relevant for arriving at a decision by the Authority:

Provided that any such study shall only be conducted on orders of the Authority.

- (xiii) to seek technical, chemical or market evaluation of any goods, which may be considered relevant in the case of any application. In the event such inquiry warrants a visit to the facilities of the applicant or to any other place, by the officers deputed by the Secretary to the Authority for the said purpose, the

expenses for the travel, other incidental expenses and/or payment of any professional fees shall be borne by the applicant:

Provided further that any such inquiry shall only be conducted on orders of the Authority.

7. Signing of Notices, etc.. - (1) Any requisition, direction, letter, authorisation, or written notice to be issued by the Authority shall be signed by the Secretary or by an officer authorised by him.

(2) Nothing contained in sub-procedure (1) shall apply to any requisition or direction which the Authority may, in the course of the hearing, issue to an applicant or a Commissioner or an authorised representative.

8. Mode of service of notices. - Every notice or other document required to be served on or delivered to any person, may be sent through process server, or by registered post or by FAX to that person or his authorised representative at the address or FAX number furnished by him for service or at the place where the person or his authorised representative ordinarily resides or carries on business or personally works for gain.

9. Procedure for filing applications. - (1) An application shall be made in Form AAR (CUS.) of the Customs (Advance Rulings) Rules, 2002 or Form AAR (CE) of the Central Excise (Advance Rulings) Rules, 2002, in quadruplicate and presented by the applicant in person or by an authorised representative to the Secretary or any other officer authorised by Secretary on this behalf or sent by registered post addressed to the Secretary along with a fee of two thousand five hundred Indian rupees in the form of demand draft drawn in favour of "Authority for Advance Rulings" payable at New Delhi.

(2) The application, its verification and the annexures, statements and documents accompanying it, shall be signed in the manner set out in the rules referred to in sub-procedure (1);

Provided that where a person signing the application and other documents claims to have been duly authorised in that behalf under the said rules, the application shall be accompanied by a power of attorney authorising him to append his signature and an affidavit setting out the unavoidable reason which entitles him to sign it.

(3) An application sent by registered post under sub-procedure (1) shall be deemed to have been made on the date on which it is received in the office of the Authority.

(4) If the applicant is not based in India, he shall indicate in Annexure I to the application,

- (a) His head office in any country,
- (b) the place where his office and residence is located or is likely to be located in India, and
- (c) the name and address of his representative in India, if any, authorised to receive notices and papers and act on his behalf.

(5) The Secretary may send the application back to the applicant if it is defective in any manner for removing the defects within such time as he may allow. Such application shall be deemed to have been made on the date when it is re-presented after correction.

10. Submission of additional facts before the Authority. - (1) The Authority may at its discretion permit or require the applicant to submit such additional facts as may be necessary to enable it to pronounce its advance ruling.

(2) Where in the course of the proceedings before the Authority, a fact is alleged which cannot be borne out by or is contrary to the record, it shall be stated clearly and concisely and supported by a duly sworn affidavit.

11. Questions contained in the application. - The applicant shall not, except by leave of the Authority, urge or be heard in support of any additional question not set forth in the application, but in deciding the application the Authority shall at its discretion consider all aspect of the questions set forth as may be necessary to pronounce a ruling on the substance of the question posed for its consideration.

12. Date and place of hearing to be notified. - (1) Where an application under sub-section (1) of section 28H of the said Customs Act or sub-section (1) of section 23C of said Central Excise Act is received from an applicant and there is no Commissioner designated as per the provisions of the Act and the rules and procedure made thereunder, a copy of the application and enclosures thereto shall be forwarded to the Board calling upon it to specify or designate, within a period of two weeks, the Commissioner for the purposes of the application failing which the application may be decided without hearing the Commissioner.

(2) On receipt of an application under sub-section (1) of section 28H of said the Customs Act or sub-section (1) of section 23C of the said Central Excise Act in respect of which a Commissioner has been designated as per the provisions of such Acts and the rules and procedure made thereunder, the authority shall notify the date and place of hearing of the application and forward a copy of the application to the Commissioner calling upon him to furnish the relevant records of the case along with his comments, if any, on the contents of the application and nominate his authorised representative if he desires to be heard.

13. Authorisation to be filed. - An authorized representative appearing for the application at the hearing shall file, before the commencement of the hearing, a document authorising him to appear for the applicant and if he is a relative of the applicant, the document shall state the nature of his relationship with the applicant, or if he is person regularly employed by the applicant the capacity in which he is at the time employed.

14. Continuation of proceedings after the death, etc. of the applicant. - Where the applicant dies or is wound up or dissolved or disrupted or amalgamated or succeeded to by any other person or otherwise comes to an end, the application shall not abate and may be permitted by the Authority, where it considers that the circumstances justify it, to be continued by the executor, administrator, or other legal representative of the applicant or by the liquidator, receiver or assignee, as the case may be, on an application made in this behalf.

15. Hearing of application. - (1) On the day fixed, or any other day to which the hearing may be adjourned, the Authority shall hear the applicant or his authorized representative in cases where it is proposed to reject the application or the applicant seeks/has sought an opportunity of being heard. The Authority may also hear the Commissioner or his authorized representative as well if it considers it necessary before pronouncing its advance ruling.

(2) In appropriate cases the Authority may call upon any person to supply such material, as it may consider necessary to assist the Authority in arriving at a decision.

(3) The Authority may, on such conditions as the circumstances of the case may require, adjourn the hearing of the application.

16. Hearing of application ex parte. - Where on the date fixed for hearing or any other day to which the hearing may be adjourned, the applicant or the Commissioner does not appear in person or through an authorized representative when called on for hearing, the Authority may dispose of the application ex parte on merits:

Provided, that where an application has been disposed of as above and the applicant or the Commissioner, as the case may be, applies within 15 days of receipt of the order and satisfies the Authority that there was sufficient cause for his non-appearance when the application was called upon for hearing, the Authority may after allowing the opposite party a reasonable opportunity of being heard, make an order setting aside the ex parte order and restore the application for fresh hearing.

17. Modification of the order. - Where the Authority finds *suo motu* or on a representation made to it by the applicant or the Commissioner or otherwise, but before the advance ruling pronounced by the Authority has been given effect to by the assessing officer, that there is a change in law or facts on the basis of which the ruling was pronounced, it may by order modify such ruling in such respects as it considers appropriate, after allowing the applicant and the Commissioner a reasonable opportunity of being heard.

18. Rectification of mistakes. - (1) The Authority may, with a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it before the ruling pronounced by the Authority has been given effect to by the assessing officer.

(2) Such amendment may be made *suo motu* or when the mistake is brought to its notice by the applicant or the Commissioner, but only after allowing the applicant and the Commissioner a reasonable opportunity of being heard.

19. Amendment of the Record. - If at any stage of the proceedings before the Authority it appears that there is any factual or material error in the records the same shall be amended after hearing the applicant and the Commissioner.

20. Fee for supply of additional certified copies. - (1) The Secretary may order grant of additional certified copies of documents or orders to the applicant or the Commissioner on a written request made by either of them.

(2) Copying fees for supply of additional certified copies to the applicant shall be charged at rupees three per page and such fees shall be paid in advance in cash.

21. Inspection of records and fees thereof. - (1) The applicant or the Commissioner or an authorized representative may be allowed to inspect the records of the case on making an application in writing to the Secretary provided that only those documents shall be allowed to be inspected which have been relied upon in the proceedings before the Authority.

(2) The inspection shall be allowed only in the presence of an officer of the Authority and the applicant may be permitted to make notes of inspection but not to take copies of any document.

(3) Fee for inspecting records of the Authority shall be charged from the applicant as follows:-

(a) Rupees one hundred for the first hour or part thereof; and

(b) Rupees fifty for every additional hour or part thereof.

(4) Fees for inspection shall be paid in advance in cash.

22. **Declaration of advance ruling to be void in certain circumstances.** - (1) Where a representation is made to the Authority by the Commissioner of Customs or Commissioner of Central Excise or otherwise, that an advance ruling pronounced by it under sub-section (6) of section 28-I of the said Customs Act or under sub-section (6) of section 28D of the said Central Excise Act has been obtained by the applicant by fraud or misrepresentation of facts, such representation shall be made in quadruplicate and shall be accompanied by a statement of facts incorporating the fraud or misrepresentation as also particulars of the evidence to substantiate the claim of fraud or misrepresentation of facts.

(2) On receipt of such representation a notice shall be issued to the applicant along with a copy of the representation for rebuttal and reasonable opportunity shall be allowed to the applicant and the Commissioner for being heard before passing an order under sub-section (2) of section 28-I of the said Customs Act or sub-section (2) of section 23D of the said Central Excise Act, as the case may be.

23. **Proceedings not open to the public.** - Proceeding before the Authority shall not be open to the public and no person other than the applicant, the Commissioner or their authorized representatives shall, without the permission of the Authority, remain present during such proceedings.

24. **Publication of orders.** - Such of the orders of the Authority, as the Chairperson deems fit for publication in any authoritative report or the press, may be released for such publication on such terms and conditions as the Chairperson may specify.

25. **Authentication and communication of orders.** - (1) Every order of the Authority shall be duly signed by the members and bear the official seal of the Authority.

(2) One certified copy of such order of the Authority shall be communicated to the applicant and the Commissioner under the signature of the Secretary or any other officer of the Authority authorised by him in this behalf and bear the official seal of the Authority.

26. Proceedings of Authority. - (1) When one or both of the members of the Authority other than the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause or in the event of occurrence of any vacancy or vacancies in the office of the members and the case cannot be adjourned for any reason, the Chairperson alone or the Chairperson and the remaining member may function as the Authority.

(2) Subject to the provisions of sub-procedure (3), in case there is difference of opinion among the members hearing an application, the opinion of the majority of members shall prevail and orders of the Authority shall be expressed in terms of the view of the majority but any member dissenting from the majority view may record his reasons separately.

(3) Where the Chairperson and one other member hear a case under sub-procedure (1) and are divided in their opinion, the opinion of the Chairperson shall prevail.

27. Procedure in case of other application. - The provision contained in these procedural rules for the hearing and disposal of application under sub-section (1) of section 28H of the said Customs Act or under sub-clause (1) of section 23A of the said Central Excise Act shall apply *mutatis mutandis*, to the hearing and disposal of all other applications, petitions and representations before the Authority.

28. Dress regulation. - (1) An authorized representative shall appear before the Authority in dress prescribed for the members of his profession by the competent professional body, if any.

(2) All other persons appearing before the Authority shall be properly dressed.

[F. No. 16/02/2002-AAR]
VIJAI LAKSHMI SHARMA, Commissioner